



जो खुद पंजाब में खेमेबाजी में लगे हैं, वो राजस्थान में पार्टी में एकता कैसे लाएंगे?

पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस में सभी को यही चिंता सता रही है

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान के प्रभारी एआईसीसी महासचिव एस.एस. रंधावा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल लिया है। रंधावा जयपुर आने वाले हैं, जहां उन्हें विभिन्न जिलों में आपस में लड़ रहे कांग्रेस नेताओं के बीच एकता कायम करने की कोशिश करनी है।
रंधावा राजस्थान में पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा के पूर्ण समर्थन में है। दोनों जाट हैं और दोनों मिलकर राज्य में दूसरे समुदायों को पीछे धकेल कर जाटों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहे हैं।
लेकिन अपने गृह राज्य पंजाब में रंधावा असहमति, गुटबाजी और खींचतान के केन्द्र बन गए हैं और उन्होंने पंजाब के पीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
राजस्थान के कांग्रेस नेता अब उन पर उंगली उठा रहे हैं और उन्हें पाखंडी बता रहे हैं।

- चिंता का विशेष कारण यह है कि रंधावा, चूंकि राजस्थान के प्रभारी महासचिव हैं, इसलिए राज्य के पंचायत चुनावों में टिकट वितरण की जिम्मेवारी उन्हीं पर रहेगी।
- चर्चा है कि पंजाब में रंधावा, अमित शाह से मुलाकात के बाद चन्नी के साथ मिलकर पंजाब के पीसीसी अध्यक्ष राजा वडिंग के खिलाफ गुटबाजी कर रहे हैं।
- यह भी चर्चा थी कि पंजाब में उनके बगावती तेवरों के कारण उन्हें राजस्थान के प्रभारी पद से हटाया जाएगा, पर, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन पर वेणुगोपाल का हाथ है।

उनका सवाल है कि जब रंधावा खुद राजस्थान और पंजाब, दोनों राज्यों में एक-एक गुट के नेता बने हुए हैं, तो वे कांग्रेस के विभिन्न गुटों के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं।
राजस्थान कांग्रेस कई गुटों में बंट चुकी है : अशोक गहलोत, डोटासरा, जूली, सचिन पायलट और इसी तरह

के कई अन्य गुट हैं।
सवाल यह उठ रहा है कि क्या राजस्थान में होने वाले महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनाव में टिकट बांटने के मामले में रंधावा सभी के साथ न्याय कर पाएंगे।
नेताओं का कहना है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए यह चुनाव बेहद

महत्वपूर्ण है। चूंकि भाजपा हर दिन कमजोर होती जा रही है, इसलिए कांग्रेस के पास अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है। लेकिन पार्टी नेतृत्व का अभी राज्य के मुद्दों पर ध्यान नहीं है।
रंधावा के पाला बदलने, और कथित तौर पर अमित शाह के कहने पर पीसीसी अध्यक्ष राजा के बजाय चन्नी का साथ देने के बाद, जोरदार चर्चा थी कि उन्हें राजस्थान के प्रभारी पद से हटाया जा सकता है।
लेकिन अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो सवाल यह है कि उनके साथ क्या किया जाएगा?
और इसके अलावा, वेणुगोपाल लगातार उनका बचाव कर रहे हैं।
रंधावा का जयपुर दौरा, जो कल होना था, अब 17 तारीख तक टाल दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या वे खुद को एक ऐसे निष्पक्ष और निर्गुट नेता के रूप में पेश कर पाते हैं, जो सिर्फ जाट नहीं, बल्कि कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ न्याय कर सके।

सरकार ने एफसीआर बिल पारित कराने के लिए जेपीसी का रास्ता चुना

सरकार ने विदेशी फंडिंग के नियमन को कठोर बनाने के लिए यह संशोधन किया और इसके लिए वह हितधारकों की चिंताओं और राजनैतिक प्रभावों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। मोदी सरकार द्वारा फॉरेन कॉन्ट्रीव्यूशन (रैम्युलेशन) अमेंडमेंट बिल (विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक), 2026 को जाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) के पास भेजने का फैसला इस बात का संकेत है कि सरकार विदेशी फंडिंग के नियमन को और कड़ा करते हुए, संसदीय गतिरोध, हितधारकों की चिंताओं और राजनीतिक प्रभावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।
25 मार्च, 2026 को लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मुख्य रूप से एफसीआरए, 2010 में संशोधन करना है। इसके तहत, एक निर्दिष्ट प्राधिकरण (डेंजिमेंटेड

- सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर कड़ी निगरानी को विधेयक का मुख्य आधार बताया है।
- विपक्षी दलों का आरोप है कि यह विधेयक गैर सरकारी संगठनों, अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है।

अर्था(रटी) गठित करने का प्रस्ताव है, जो किसी संगठन का पंजीकरण रद्द होने, स्वेच्छा से वापस लिए जाने या उसकी अवाधि समाप्त होने की स्थिति में विदेशी अंशदान और उससे बनाई गई संपत्तियों का प्रबंधन तथा निपटान करेगा।
सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य उन प्रशासनिक खामियों को दूर करना है, जिनके कारण अनिश्चितता और संभावित दुरुपयोग की स्थिति पैदा

होती है। इसके तहत, संपत्तियों को अस्थायी रूप से सरकार के अधिकार में रखने और संगठन का पंजीकरण दोबारा बहाल होने पर उन्हें वापस करने का प्रावधान होगा। साथ ही, पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को सुरक्षित रखने और, समुदाय या विचारधारा की परवाह किए बिना, सभी संगठनों पर नियम समान रूप से लागू करने की बात कही गई है।
(श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

रूस ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ बनाया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। “बार एंड बेच” की रिपोर्ट के अनुसार, “रलोबल आर्बिट्रेशन रिव्यू” ने बताया है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.

- यूक्रेन के ओशादबैंक के साथ विवाद पर इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में होने वाली सुनवाई में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ को अपना प्रतिनिधि बनाया है।

चंद्रचूड़ एक इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह ट्रिब्यूनल यूक्रेन के सरकारी बैंक ओशादबैंक द्वारा लाए गए एक विवाद की सुनवाई कर रहा है। यह मामला रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और सैन्य अभियानों के कारण बैंक के कामकाज

टेक इट और लीव इट- शाह

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। लम्बी चुप्पी और दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा से गायब रहने के बाद, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि वे सदन में आने, बहस में हिस्सा लेने और उनसे पूछे जाने वाले किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
यह पेशकश संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन से एक दिन पहले आई है। पूरा सत्र लगभग बेकार चला गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों

- वी हैव लैफ्ट इट- राहुल।
- गतिरोध वैसे का वैसे बरकरार।

ही संसद के दोनों सदनों में नहीं आए। काफी आलोचना और खराब प्रचार के बाद, अमित शाह जाहिर तौर पर इस धारणा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि गृह मंत्री डरे हुए हैं और छात्रों पर पैलैट गन चलाने का आदेश किसने दिया, इस सवाल पर विपक्ष के हमले का सामना नहीं करना चाहते।
सवाल वही हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं हैं।
राहुल गांधी ने इस पेशकश को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष और देश को किसी भाषण की जरूरत नहीं है। वे पहले सवाल का जवाब चाहते हैं और उसके बाद बहस।
(श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

टाटा संस के प्रमुख चंद्रशेखरन पद त्याग करेंगे

चंद्रशेखरन ने कहा, उन्होंने यह फैसला इसलिए किया है, क्योंकि कंपनी के एक बोर्ड सदस्य ने उनके कार्यकाल विस्तार का समर्थन नहीं किया था

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने आज शेयरधारकों के साथ तनाव और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के साथ अपना कार्यकाल बढ़ाने को लेकर मतभेदों के बीच पद से इस्तीफा दे दिया।
चंद्रशेखरन ने अपने बयान में कहा कि अगले साल फरवरी में उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म होने पर वे दोबारा नियुक्ति की मांग नहीं करेंगे।
चंद्रशेखरन ने कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के एक सदस्य ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का समर्थन नहीं किया।
उन्होंने अपने बयान में लिखा, “सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से मेरे अगले कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया था और इसकी सिफारिश की थी। टाटा संस की

- चंद्रशेखरन ने कहा कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से मेरे कार्यकाल को 5 साल बढ़ाने का फैसला किया था और टाटा संस की नॉमिनेशन एंड रैम्युनेरेशन कमेटी ने भी इसे स्वीकार किया था।

- पर, जब 24 फरवरी 2026 को टाटा संस के बोर्ड के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया तो एक सदस्य ने समर्थन नहीं दिया और सर्वसम्मत समर्थन नहीं मिलने से मैंने इसे तब टाल दिया और अब 6 माह बाद भी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ है तो मैंने यह निर्णय लिया है।

नॉमिनेशन एण्ड रैम्युनेरेशन कमेटी तथा बोर्ड ने भी इसे रिफाई किया और इसकी सिफारिश की। इसके बाद यह प्रस्ताव 24 फरवरी 2026 को टाटा संस के बोर्ड के सामने रखा गया। लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, क्योंकि बोर्ड के एक सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया। सर्वसम्मत समर्थन नहीं मिलने के कारण मैंने इस फैसले को टालने का निर्णय लिया।”

चंद्रशेखरन ने कहा कि बोर्ड की बैठक को छह महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकल पाया है।
उन्होंने कहा, “टाटा संस एक बहुत बड़ा संस्थान है और कई महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाएं इस समय बेहद अहम चरण में हैं। यह जरूरी है कि फरवरी 2027 के बाद समूह का नेतृत्व करने के लिए एक नेता की नियुक्ति हो।

साथ ही नेतृत्व को लेकर स्पष्टता कर्मचारियों, निवेशकों, पार्टनर्स और अन्य स्टैक होल्डर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है।”

चंद्रशेखरन पिछले 40 वर्षों से टाटा समूह का हिस्सा रहे हैं। वे जनवरी 2017 से टाटा संस और टाटा समूह के चेयरमैन हैं। उन्होंने 1987 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में प्रशिक्षु के रूप में काम शुरू किया और 2009 में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। इसके बाद उन्होंने टाटा संस की कमान संभाली।

उन्होंने अपने बयान में कहा, “मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान में योगदान देने के बेहद संतोषजनक अवसर के लिए आभारी हूं। पिछले एक दशक में टाटा संस का नेतृत्व करना मेरे लिए बड़े सम्मान और गहरी जिम्मेदारी का विषय रहा है।”

अपने उत्तराधिकारी की प्रक्रिया के अगले कदम के बारे में चंद्रशेखरन ने

ऑटो -टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य

नई दिल्ली, 12 अगस्त। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता को और सख्त कर दिया

- सरकार ने महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम में संशोधन करते हुए चालकों के लिए मराठी जानना अनिवार्य कर दिया है, भाषा नहीं जानने पर तीन माह तक लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान बनाया।

है। बुधवार को सरकार ने महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026 में संशोधन करते हुए कड़े नियमों और दंड का प्रावधान किया है। नए नियमों में